MR. DEPUTY-SPEAKER: No, no Not necessary. Shri Kanwarlal Gupta has already explained what he has said.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE)—rose

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do you want to say anything?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I would like to take the Leader of the Opposition seriously.

I did attend the public meeting, but I did not say that the maximum punishment should be given. In fact, I said in so many words that the quantum of punishment is to be decided by Parliament, and not even by the Janata Party. When certain slogans were raised—those slogans were highly objectionable—I admonished those who were raising them, and they kept quiet. Let him go through the proceedings of the meeting. I welcome his assurance that they are opposed to violence. All parties have to exert their influence that there is no outbreak of violence in any form or in any shape because violence and democracy cannot go together.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Calling Attention; Shri Brij Bhushan Tiwari.

SHRI K. GOPOL (Karur): On behalf of the House, I congratulate Mr. Saugata Roy on his marriage.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We congratulate him.

SHRI A. BALA PAJANOR (Pondicherry): I think they can join in this. We should have unanimity at least in this respect.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री सौगत राय की आजादी खत्म हो गई इसके लिये हमें अफसोस है।

SHRI A. BALA PAJANOR: He is saying it as a bachelor.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Vajpayee, being a bachelor, feels like that.

SHRI A. BALA PAJANOR: I know, you are also a bachelor. Mr. Kamath, a senior member, is a bachelor; he is not here.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN (Satara): Mr. Vajpayee should reconsider his position now.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am told that in the confusion that was going on, one paper has not been laid—Item No. 4; Shri Shanti Bhushan.

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): Sir, on behalf of Shri Shanti Bhushan, I have already laid on the Table the paper mentioned against his name.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is all. We now take up the Calling Attention; Shri Brij Bhushan Tiwary.

12.12 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED AGREEMENT BETWEEN CHINA AND FRANCE AND SUPPLY OF NUCLEAR PLANT AND TECHNOLOGY TO CHINA BY FRANCE UNDER AUTHORISATION OF USA

श्री बृज भूषण तिवारी (खलीलाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विदेश मंत्री का ध्यान एक बहुत ही लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह उस पर सदन में बयान दें :—

> "संयुक्त राज्य अमरीका के प्राधिकार से फ्रांस द्वारा चीन को परमाणु संयंत्र और प्रौद्योगिकी की सप्लाई के लिए चीन और फ्रांस के बीच समझौते के समाचार।"

THE MINISTER OF EXAERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): As the House is aware, press reports have recently appeared stating that France and China have signed an economic agreement in Peking on December 4, 1978, regarding trade between the two countries

[Shri Atal Bihari Vajpayee]

over the next seven years. This agreement is reported to include a provision regarding the sale of nuclear power reactors to China by a Franch firm.

It has also been stated that the nuclear power reactors in question are based on technology originating in the U. S. A. While Government have seen newspapers reports that it is likely that US Government would give their clearance, which would be necessary for their export to China by France, it is understood that the question of their clearance is still under the consideration of the US Government.

Government do not yet have confirmed details and information on the scope and conditions of the reported sale of nuclear power equipment to China. In the absence of these, it is not possible to comment on the precise implications of this transfer of technology which, further, is the immediate concern of the three parties involved. However, I would like to reiterate Government's well-known views on the peaceful utilisation of nuclear energy and the necessity to ensure that any safeguards that may be eventually applied in the matter of the transfer of nuclear technology should be uniform and non-discriminatory covering all activities applicable to nuclear and non-nuclear weapon States.

श्री ब्रज भूषण तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो बयान विदेश मंत्री ने सदन में दिया है, वह काफी नहीं है क्योंकि जितना सरल इस समझौते को हम समझ रहे हैं, उतना सरल यह नहीं है। यह समझौता 4 दिसम्बर को हुआ जिसमें केवल आर्थिक पहलू ही संबंधित नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा का सवाल भी सम्बन्धित है। इसके बारे में सरकार के द्वारा यह बयान दिया जाना कि समाचार पत्रों के जरिये मुझे यह जानकारी मिली है, सचमुच में यह चिन्ताजनक बात है। इसको अमर्टेन करना चाहिये था, फ्रांस के अम्बैसेडर यहां पर हैं और हमारे अम्बैसेडर फ्रांस में हैं। इसके अलावा और भी जो हमारे साधन थे, उनके जरिये हमें इन सारे तथ्यों की जानकारी करनी चाहिये थी।

यह समझौता 4 दिसम्बर को हुआ, ऐसा नहीं है कि अचानक चीन के रुख में या अमरीका या पश्चिमी देशों के रुख में परिवर्तन आ गया क्योंकि लगातार चीन से और यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेशन्ज नार्मलाइज होते रहे हैं और आज जो यह पूरा चक्कर है, यह पूरा हो जाता है जब ताइवान को भी अमरीका ने डीरिकग्नाइज कर दिया और पूरी तरह से चीन को समर्थन दिया। इसके लिये 1975 में पीटसंवर्ग ने कहा था—

In 1975 Michael Pittsburg strongly argued for close military cooperation between the United States and China.

और इसी के साथ ही साथ अभी ब्रेजहनस्की ने पीकिंग में कहा है कि

"A secure and strong China is in America's interest."

इसी के साथ साथ अमरीका ने अपने तमाम एलाइज को यह अनुमति दी है कि वह चीन की आणविक शक्ति को बढ़ाने के लिये, उसकी वेपन पावर्स को बढ़ाने के लिये आधुनिक सुविधाएं दे सकते हैं, पैसा और मशीनरी दे सकते हैं।

इसी सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण सूचना है, मैं चाहूंगा कि सरकार उस सम्बन्ध में भी अपनी सफाई दे क्योंकि मिराज एफ–1 को वैसे ही फ्रांस ने भी इन्कार किया, परन्तु यह जानकारी मिल रही है कि उसकी एक फैक्टरी पाकिस्तान में खुलने जा रही है और चीन बजाय फ्रांस से सीधा समझौता करने के पाकिस्तान के मारफत ऐसे लड़ाकू विमान खरीद सकता है या उसको बनाने की तकनीकी अपने यहां ले सकते हैं।

यह सारी चीजें इसलिये भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि चीन और पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद बदस्तूर है और अभी कराकोरम की जो सड़क बनाई गई है और उसी के साथ-साथ चीन का जो काश्मीर के बारे में दृष्टिकोण है कि वे सैल्फ डिटरमिनेशन के प्रिंसिपल को स्वीकार करते हैं और इस सम्बन्ध में पाकिस्तान को पूरा समर्थन देने का वायदा करते हैं। उसके साथ ही साथ चीन का रुख हमारे नार्दन हिल, जो पूर्वी सीमान्त है वहां पर टाइल्स को ट्रेनिंग देने में पूरा हाथ है। इसके साथ ही साथ उनसे हमारा सीमा विवाद बदस्तूर है। तो यह सारे तथ्य और सन्दर्भ हैं और चीन व अमरीका की मिली हुई साजिश कि यह जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, जो एशियन रीजन है, जो पावर ब्लाक है, शक्ति संतुलन हुआ है, उसे डिस्टर्ब किया जाये और ऐसा शक्ति संतुलन बनाया जाये ताकि एक तरफ अमरीका द्वारा चीन से रूस को आइसोलेट करना है और दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के ऊपर बराबर यह खतरा बनाये रखना है। उनकी शर्तों पर हम हमेशा चलते रहे और समझौता करते रहे।

इसके साथ तमाम अमरीकी जो शिक्षा-विद हैं इंटलैक्चुअल्स हैं, इन्टैलीजैन्सिया है, वह भी काफी पैमाने पर भारत में आ रहे हैं। चाइना कार्ड का इस्तेमाल किया जाय, वह सारी की सारी मशीनरी पर भी अपना दबाव का इस्तेमाल करती है और इसके साथ उन्होंने चीन के साथ सम्बन्धों को ठीक करने के लिये वकालत शुरू की है, मैं भी इस पक्ष में हूं। हमारी सरकार ने—हमारे

प्रधान मंत्री जी और विदेश मंत्री ने—घोषणा की है कि हम विवाद को शन्तिपुर्ण तरीके से हल करना चाहते हैं । लेकिन हुआ साहब ने कहा है कि भारत कन्क्रीट प्रापोजल्ज लेकर आये कि हम सीमा-विवाद को कैसे हल कर सकते हैं । जब एकेडेमीशन्ज का ऐसा दबाव पड़ रहा है और जो लोग आज वाशिगटन में बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं, वे इस कोशिश में हैं कि चीन की ताकत बराबर बढ़ती रहे, निरंकुश रूप से बढ़ती रहे, तो वह खतरा सदा बरकरार रहेगा कि भारत को दबाया जाय, उसको कमजोर बनाया जाय । मैं विदेश मंत्री से साफ तौर पर पूछना चाहता हूं कि क्या यह न्युक्लीयर क्लब के मेम्बरों की सजिश का ही एक अंग तो नहीं है कि अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर इस लिए दबाव डाला जाय कि उसने अपने आणविक संयंत्रों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण एवं सर्वेक्षण को स्वीकार नहीं किया है ? क्या पाश्चात्य देशों की यह नीति तो नहीं है कि भारत पर इस लिए भी दबाव डाला जाय कि भारत को चीन के निकट आने के लिए मजबूर किया जाय, ताकि भारत और रूस के बीच घनिष्ठ सम्बन्धों में फर्क आये और इस क्षेत्र में एक दूसरे प्रकार के शक्ति-गुट या पावर-ब्लाक का निर्माण हो ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने भारी स्थिति पर गम्भीर चिन्ता प्रकट की है । हम लगातार इस मामले में पैरिस-स्थित अपने दूतावास के जरिये फ्रांस की सरकार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं । उसके अनुसार अभी तक राजनैतिक, वित्तीय तथा तकनीकी—पोलीटिकल, फिनांशल एंड टेकनिकल—डीटेल्ज अन्तिम रूप से तय नहीं हुई है, और जब तक ये तय नहीं होंगी, तब तक ऐसा नही माना जाना चाहिए कि समझौता हो गया ।

इस मामले में अमरीका भी एक पक्ष है, क्योंकि अमरीका के यहां से टेकनालोजी को जाना है । चीन कम्युनिस्ट देश है, और अगर अमरीका द्वारा दी गई टेकनालोजी फ्रांस के माध्यम से चीन पहुंचती है, तो इसके लिए अमरीका की स्वीकृति की जरूरत है । कल भी अमरीकी दूतावास के साथ इस बारे में बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि अभी तक हमने क्लीयरेंस नहीं दिया है ।

माननीय सदस्य ने कुछ और मामले उठाये हैं । मैं समझता हूं कि वे इससे सीधे सम्बन्धित नहीं हैं । अभी परसों विदेश नीति पर, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर, चर्चा होगी, तो हम इन सारे मामलों पर गहराई से विचार कर सकेंगे ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच) : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेंट मंत्री महोदय ने दिया है, वह सचमुच मेरे लिए भी आश्चर्यजनक है, और वह इस लिए कि जो न्युक्लीयर प्लांट दिया गया है, और जो टेकनालोजी के बारे में बातचीत चल रही है, यह तो निश्चित है कि यह प्लांट व टैकनालाजी चीन को दी जायगी । मंत्री महोदय को भले ही संदेह हो, परन्तु अमरीकी गवर्नमेंट ने चाइना को न्यूक्लीयर प्लांट, अस्त्र-शस्त्र और टेकनालोजी से माडर्नाइज करने और रूस के खिलाफ एक बड़ी शक्ति के रूप में चीन को खड़ा करने का निश्चय कर लिया है । इसी नीति के अनुसार उसने अपने मित्र देशों को, जिनके पास यह ज्ञान है, जहां जहां, इस प्रकार के न्यूक्लीयर प्लांट हैं, यह ज्ञान और टेकनालोजी पीकिंग को देने की अनुमति देने का निश्चय कर लिया है । अभी चाहे अमल न हो परन्तु यह उन की नीति के अनुसार है । मैं यह कहना चाहूंगा आप से, अमेरिका ने हमारे तारापुर प्लांट के लिए एनरिच्ड यूरेनियम देने के समय और फिर अगला जो हमारा इस्टालमेंट है जिस के लिए ऐग्रीमेंट हो चुका है, उस ऐग्रीमेंट के अनुसार उस को यह एनरिच्ड यूरेनियम देना है लेकिन वह इसलिए देने को तैयार नही है कि हम ने सेफगार्डस स्वीकार नहीं किये और नान-प्रालिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नही किए । अमेरिका में एक इस प्रकार का लेजिस्लेशन भी पास हुआ है कि इस प्रकार के देशों को टेक्नोलाजी और एनरिच्ड यूरेनियम न दी जाय जब तक वे इस प्रकार के सेफगार्डस स्वीकार न करें, हमें भी वह इस लिए नही दे रहे हैं लेकिन चाइना को इस प्रकार की टेक्नोलाजी देने की बात हो रही है और यह न्युक्लियर प्लांट जा रहा है, यह बात डेफिनिट है तो इस प्रकार का जो भेदभाव अमेरिका सरकार कर रही है, यह जो उस की दोहरी और दोमुखी नीति है उस के बारे में क्या सरकार ने अमेरिका सरकार से जानकारी प्राप्त की है कि उन की इस प्रकार की दोमुखी नीति क्यों है, एक समान नीति क्यों नही है ? जहां जहां भी इस प्रकार की टेकनोलाजी वह देंगे और इस प्रकार का न्युक्लियर प्लांट जायेगा वहां इस प्रकार की बात हो सकती है क्योंकि इसमें प्लूटोनियम भी पैदा होता है जिस से ऐटम बम बनता है । हमारे यहां उस की जानकारी है क्योंकि जो स्पेंट फ्यूएल बचेगा उस की रिफ्यूएलिंग से प्लूटोनियम पैदा होता है जिस से ऐटम बम बनेगा । इसलिए यह कोई साधारण बात नही है । मैं यह कहना चाहूंगा सरकार से, यह फ्रांस गवर्नमेंट का सवाल नही है, यह सवाल सीधा अमेरिका गवर्नमेंट का है । क्या आप ने अमेरिकन गवर्नमेंट से बाकायदा उन की इस नीति की चर्चा की है या नही की है कि क्या उन की इस संबंध में यूनिफार्म नीति रहेगी या इस प्रकार की दोमुखी नीति रहेगी और वह हम को भी इसी आधार पर देंगे या नही देंगे ?

दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि अमेरिका चाइना को मजबूत बना रहा है, यह बात नही है और उन की अन्तरराष्ट्रीय नीति का यह अंग है । ठीक है, इंडिया के खिलाफ पैरलल पावर

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

खड़ी कर रहे हैं, हमें इस में आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं आप से कि जो इस प्रकार से चाइना को सशक्त बनाया जा रहा है और चाइना एक ओर पाकिस्तान को आणविक ज्ञान देने का प्रस्ताव कर चुका है, आणविक क्षेत्र में जो टेक्नालाजी चाइना के पास है उस में आलरेडी 40 प्लांट एटम बम बनाने के लिए उस के पास हैं, केवल पीसफुल इस्तेमाल एटामिक एनर्जी उत्पन्न करने की टेकनिकल नो हाउ उस के पास नहीं है, इसलिए उस ने अमेरिका की शरण ली है और यह भी उस को मिल जाती है तो एटामिक एनर्जी के और उसके टेकनिकल ज्ञान से वह पूर्ण हो जाता है और यह उस की नीति है, मैं आप से कहना चाहता हूं कि माऊ का जो डिक्टम है रेस्पेक्ट दि एनीमी टैक्टिकली ऐंड डेस्पाइज हिम स्ट्रेटेजिकली, यह उस की नीति है, उसी नीति के अनुसार अमेरिका के साथ उस का समझौता चल रहा है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान को वह इस प्रकार का आफर कर चुका है, दूसरी ओर नागालैंड और मिजोरम के विद्रोहियों को वह हमारे खिलाफ सहायता कर रहा है, और अब यह शक्ति वह प्राप्त कर रहा है तो क्या इस प्रकार के समझौते से अन्तरराष्ट्रीय राजनीति पर कोई फर्क या कोई कुप्रभाव पड़ने की कोई संभावना है या नहीं है और दूसरे क्या हमारी डिफेंस पर भी इस का कोई असर पड़ेगा ? इस देश की सुरक्षा पर, इस देश की नीति पर और चाइना और भारत के सम्बन्धों पर भी इस का कुप्रभाव पड़ने की कोई संभावना है या नहीं ? यदि है तो हमारी सुरक्षा के लिए आप ने क्या किया है? ऐसा कुप्रभाव न पड़े, इस दिशा में आप ने क्या प्रयत्न किया है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। यदि अमेरिका फ्रांस के जरिये चीन को ऐसी टेकनोलाजी देता है जो साधारणतः अमेरिका और देशों को नहीं देता है और अगर देता है तो उन पर यह शर्त लगाता है कि पाने वाले देश के एटामिक रिएक्टर फुल स्कोप सेफ गार्डस में आएंगे। तो चीन के सम्बन्ध में कोई भी भेदभाव करना, यह गलत होगा और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। चीन के पास एटम बम हैं, अक्तूबर, 1964 में चीन ने पहला अणु विस्फोट किया था। हथियारों की दिसा में चीन ने काफी प्रगति की है लेकिन इस सवाल पर चर्चा करते समय हम उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं। माडर्नाइजेशन के लिए अगर चीन अणु शक्ति चाहता है तो देने वाले देश का यह कर्तव्य है, विशेषकर अमरीका का, कि वह देखे कि कोई भी ऐसी फुल स्कोप सेफगार्डस के अन्तर्गत वह रहना चाहिए जैसे कि तारापुर में है जिससे एटामिक इंस्टालेशन का उपयोग ऐसे तत्व या ऐसे यूरेनियम से प्लूटोनियम बनाने में बचे न हो जिस कि हथियारों के विस्तार के कार्यक्रम को और भी बल मिले। इस विषय में मैं सदन को विश्वास में लेना चाहूंगा। माननीय सदस्यों ने भी सिनेटर फ्रैंक चर्च जो फारेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन हैं, के एक वक्तव्य को देखा होगा। उनके कुछ वाक्य मैं उद्धृत करना चाहता हूं :

"There is a real possibility of selling commercial nuclear reactors to the Chinese. Remember that since the Chinese have already developed a full capacity to manufacture nuclear weapons the normal concern that we have about proliferation of such weapons is not present in the Chinese case."

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति हास्यास्पद है। एक ओर तो अमरीका प्रोलिफरेशन को रोकना चाहता है और दूसरी ओर प्रोलिफरेशन को रोकने सम्बन्धी जितनी भी शर्तें हैं वह ऐसे देशों पर लगाना चाहता है जिन्होंने पहले से ही फैसला किया है कि हम आणविक हथियार नहीं बनायेंगे। मैं समझता हूं माननीय सदस्य का यह आरोप ठीक है कि अमरीका इस सबन्ध में दोहरे माप-दण्ड का उपयोग कर रहा है। इस माप-दण्ड का उपयोग नहीं होना चाहिए और भारत उसका विरोध करेगा।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या इस प्रकार के समझौते से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र और भारतवर्ष पर कोई कुप्रभाव पड़ने की सम्भावना है या नहीं ? यदि है, तो उसको दूर करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, भारत अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत है। पड़ौस में होने वाली सारी घटनाओं को ध्यान में रखकर हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर निरन्तर विचार करते रहते हैं और जहां भी कमी दिखाई देती है उसको पूरा करते हैं।

श्री उग्रसेन (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो सदन के सामने रखा गया है, माननीय मंत्री जी जब अभी जनवरी में चीन जा रहे हैं उसके सन्दर्भ में यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाना है। मैं तीन बातों की ओर विदेश मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मैं 27 नवम्बर के यू एन आई के एक समाचार की दो तीन लाइनें पढ़ देना चाहता हूं ताकि मंत्री जी और सरकार इसको समझ ले। यह यू एन आई की रिपोर्ट है :

"The reported agreement by China to acqquire a sophisticated nuclear plant from France and its arms deals with various western

countries have created a serious situation in the sub-continent."

पश्चिमी देशों से चाइना ने हथियार लेने के जो समझौते किए हैं और अमरीका के साथ उन्होंने न्यूक्लियर आर्म्स लेने की बात की है यह बहुत खतरनाक स्थिति है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या वे इस बात को मानते हैं-- वे ठीक ठीक बतायें--क्या यह अमरीकी साम्राज्यवादियों की साजिश है कि हिन्दुस्तान को चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले कमजोर करने के लिए चीन को हम मदद दें ? इस पर आप प्रकाश डालें कि हमारी नीति क्या है ?

दूसरी बात यह है कि चीन के हुआ कुवो फेंग ने पीकिंग में कहा है कि हमने निश्चय किया है कि पश्चिमी देशों से, जहां कहीं से भी हो, हम आधुनिकतम हथियार, आणविक हथियार मंगायेंगे और उसी योजना के अन्तर्गत समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार चीन की सरकार ने फ्रांस से समझौता किया है ।

तीसरी बात यह है क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि चाइना ने यूरोपियन एकोनामिक मार्केट से भी मोस्ट माडर्न वीपन्स खरीदने का एक समझौता किया है ? क्या मंत्री जी इस बात को मानते हैं कि आधुनिकतम आणविक हथियार और दूसरे किस्म की ऐसी आणविक भठ्ठियां अगर साम्राज्यवादी देश यूरोपियन एकोनामिक मार्केट के नेतृत्व में चीन को दे देंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है, और चीन के पास एटम बम है ही तो उस हालत को देखते हुए क्या मंत्री जी अपने यहां डिफेन्स मिनिस्टर का सुरक्षा की बातों की तरफ ध्यान आकृष्ट करेंगे और उसके लिए तैयारी का सुझाव देंगे ?

मेरी यह मान्यता है और मैं दृढ़-निश्चित हूं कि अमरीका और पश्चिमी देश हिन्दुस्तान को, जो एक जनतन्त्रीय देश है, उस को कमजोर करने के लिये चीन को उभार रहे हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल रूस से मुकाबले की बात नहीं है, बल्कि वे साठ करोड़ की धरती पर गलत निगाह लगाये हुए हैं । चूंकि माननीय मंत्री जी चीन जा रहे हैं--रास्ते में अखबार वाले हवाई अड्डे पर उन से पूछेंगे--चीन कम्बोडिया को उभार कर वियतनाम के साथ जो कर रहा है, उस ने हमारी जमीन को हड़प लिया है, बर्मा के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, चारों तरफ हाथ मार रहा है, पाकिस्तान को उभार कर लड़ा रहा है--चाइनीज कम्यूनिस्ट पार्टी की दो नीतियां हैं--समाजवादी और साम्राज्यवादी, रूस भी यही करता है और चीन भी यही करता है--उस की कम्यूनिज्म की समाजवादी और साम्राज्यवादी नीति को छोड़ दीजिए--लेकिन जो उस की एक्सपांशनिस्ट नीति है--उस के बारे में हमारी सरकार क्या सोच रही है ? मंत्री जी जब उधर जायेंगे तो उन को संयुक्त-विज्ञप्ति लिखनी पड़ेगी--मैं जानना चाहता हूं कि उस के लिये आप क्या दिमाग बनायेंगे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने स्पष्ट किया--इस प्रश्न के दो पहलू हैं--एक चीन के पास आणविक हथियार हैं और चीन उन हथियारों का विकास कर रहा है और चीन जो भी स्रोत उपलब्ध हैं उन से अपनी प्राद्योगिकी का विस्तार करने में संलग्न है ।

दूसरा पहलू--यह है कि अगर अमरीका उस शर्त की अवहेलना कर के जो वह हमारे ऊपर लगा रहा है--तारापुर के सम्बन्ध में एन-रिच्ड यूरेनियम देने के बारे में--वह शर्त अगर चीन पर नहीं लगाता--यह कह कर कि चीन के पास पहले से ही एटामिक हथियार हैं--इस लिये उस पर शर्त लगाने की जरूरत क्या है ? यह हमारे लिये न केवल चिन्ता का विषय है, बल्कि हमारे लिये असन्तोष का विषय भी है और हम अपनी भावना अमरीकी सरकार को असंदिग्ध शब्दों में बतला रहे हैं--केवल उन देशों के बारे में "फुल-स्कोप-सेफगार्डस" नहीं हो सकते जिन के पास हथियार नहीं हैं, उन पर सेफ-गार्डस लगाने की जरूरत क्या है--हम ने तो पहले ही एलान कर दिया है ....

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : आप भी बनाइये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या अमरीका यह चाहता है ? मैं नहीं समझता कि अमरीका यह चाहता है, मगर जो अमरीका नहीं चाहता है, आज उस से उलटा काम कर रहा है ।

श्री ब्रज भूषण तिवारी : अगर आप रूस से लड़िये तो चाहेगा ।

एक माननीय सदस्य : आप यह भावना व्यक्त कर दीजिये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह भावना व्यक्त नहीं होती है, सरकार की नीति की उद्घोषणा होती है । संसद में भावना ही व्यक्त की जाती है, हाथापाई नहीं की जाती है । इतने बड़े देश के, इतने शक्तिशाली देश के, जिस देश में इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हों, उन के प्रवक्ता के रूप में अगर मैं कुछ कहता हूं--तो वह मात्र भावना का प्रकटीकरण नहीं है, वह समूचे भारत की आवाज है.....

डा० कर्ण सिंह (उधमपुर) : भावना से कर्तव्य ऊंचा होता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कर्तव्य का क्षण जब आयेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब उग्रसेन जी ने पूछा कि चीन अलग-अलग ढंग से तैयारी कर रहा है,

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

पाकिस्तान को भी वह बीच में लाये और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का भी उल्लेख किया—मैं समझता हूं ये सारे मामले यद्यपि] महत्वपूर्ण हैं, मगर सीधे इस में से नहीं निकलते हैं और जैसा मैंने कहा है—परसों हम अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर एक विवाद चर्चा करने वाले हैं, उस में ये सारे मामले उठाये जा सकते हैं ।

श्री हरकेश बहादुर (गोरखपुर) : मान्यवर, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सभी प्रश्नों को माननीय मंत्री जी के सामने रखा और माननीय मंत्री जी ने भी बहुत सी बातों का जवाब दिया । लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैं भी उनके सामने रखना चाहता हूं ।

जो कुछ भी समझौता हुआ फ्रांस और चीन के बीच और यह अमेरिका की सहमति से समझौता हुआ । क्या इस समझौता से भारत की सुरक्षा और विदेश नीति दोनों पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा ? यह न केवल भारत की सुरक्षा और विदेश नीति पर बल्कि दुनिया के अन्दर चीन और अमेरिका के बीच सम्बन्ध कायम होने के बाद पूरी विश्व की राजनीति के आयाम ही क्या नहीं बदलेंगे ?

यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आज अमेरिका जो कार्य कर रहा है उस से साफ जाहिर है कि वह दोहरी नीति अपना रहा है । 1954 में जब राष्ट्रपति आइजनहावर ने भारत से कहा था कि भारत को चाहिए कि साम्यवादी देशों के प्रसार को रोकने के लिए भारत हथियार ले तो उस समय भारत ने उसे अस्वीकार कर दिया था । उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी और आज की राजनीतिक स्थिति क्या है ? राष्ट्रपति कार्टर चीन की आयुध शस्त्र शक्ति, सामरिक शस्त्र शक्ति और दूसरी शस्त्र शक्ति को बढ़ाने के लिए चीन को मदद देने के स्तर तक उतर आये हैं । इस से साफ जाहिर है कि भारत के प्रति इन लोगों का इरादा साफ नहीं है । वे भारत को कमजोर बनाना चाहते हैं और भारत को ही नहीं, भारत से सम्बन्धित जितने भी राष्ट हैं जिन के साथ भारत के अच्छे सम्बन्ध हैं उन को भी कमजोर करना चाहते हैं ।

जहां तक सोवियत संघ का सम्बन्ध है, उन्हें मालूम है कि चीन के साथ भी सोवियत संघ के सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे हैं और भारत के साथ चीन के सम्बन्ध पिछले कई वर्षों से तनावपूर्ण चले आ रहे हैं । इसलिए सोवियत संघ और भारत दोनों को कमजोर करने की दिशा में यह उनकी साजिश है । भारत रूस मैत्री इतिहास की सच्चाइयों एवं वास्तविकता पर आधारित है । हमें रूस के साथ अपने सम्बन्ध निरन्तर कायम रखने और उन्हें उत्तरोत्तर मजबूत बनाते रहने की आवश्यकता है । चीन-अमेरिका सम्बन्ध सोवियत संघ को नीचा दिखाने और भारत की स्थिति को कमजोर करने की दिशा में एक बहुत बड़ा अन्तर्राष्टीय राजनीतिक षड़यंत्र प्रतीत होता है ।

मान्यवर, इन सच्चाइयों के तहत, मैं सिर्फ बात को माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर हमारे तारापुर के एटोमिक प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट को जिस को 1994 तक अमेरिका द्वारा यूरोनियम देने का समझौता हुआ था, उसे आज अमेरिकी राष्ट्रपति स्वीकार करने को क्यों नहीं तैयार हैं ? अगर वे स्वीकार भी करते हैं तो उन के देश की जो अन्य संस्थाएं हैं, जो इसे देती हैं या इसको देने की अनुमति प्रदान करती हैं उन पर वे क्यों नहीं अपना दबाव डाल पा रहे हैं ? मेरे पास जो कटिंग है उस में साफ लिखा है–

> "The US president, Mr. Jimmy Carter, ovefriding State Department objections has authorised France to sell American-llicensed nuclear reactors to China."

वे चीन के साथ इस तरह का समझौता कर सकते हैं लेकिन तारापुर पावर प्लांट के लिए यूरेनियम देने में उन्हें हिचकिचाहट हो रही है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि क्या वे राष्ट्रपति कार्टर को पत्र लिख कर उन से यह स्पष्ट जानना चाहेंगे कि अमेरिका चीन की परमाणु शक्ति को बढ़ा कर क्या भारत और विश्व शांति के लिए खतरा पैदा नहीं करना चाहता है ? क्यों भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के साथ किये गये वायदे को भी पूरा नहीं किया जा रहा है जबकि चीन को हथियारों के मामले में मजबूत करने से भारत की सुरक्षा को खतरा होगा । क्या अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के साथ मैत्री रखने का इरादा छोड़ चुके हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, तारापुर के सम्बन्ध में अमेरिका के साथ हमारा जो समझौता हुआ हैं उस समझौता का पालन होना चाहिए । अमेरिकी कांग्रेस ने जो कानून बाद में पारित किया है, उस कानून को उसके बनने से पहले हुए समझौते पर लागू नहीं किया जा सकता । हमें एक किस्त मिल गयी है, दूसरी किस्त मिलेगी, इसकी हम आशा करते हैं । इस सम्बन्ध में प्रेजिडेंट कार्टर का रुख सहायक है, यह हमें मालूम है । लेकिन वहां और भी एजेन्सियां हैं जो इस मामले में आपत्तियां करती रहती हैं । वह एक लोकतंत्रवादी देश है लेकिन उस सब के बावजूद हमें आशा है कि अमेरिका हमारे साथ किये गये करार का पालन करेगा और अगर नहीं करेगा तो हम तारापुर को चलाने के लिए अन्य स्त्रोतों से इंतजाम करने के लिए स्वतंत्र होंगे । माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या प्रेसीडेंट कार्टर की चिट्ठी लिखी जयगी ? अब प्रेसीडेंट कार्टर और प्रधान मंत्री के बीच में पत्र-व्यवहार चलता रहता है, उसमें अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा होती है, द्विपक्षीय मामलों पर भी विचार विनिमय होता है । और मैं समझता हूं कि जब यह मामला अन्तिम रूप लेगा तो इस मामले को भी उच्च स्तर पर उठाया जा सकता है ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (फरीदकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के पड़ोसियों के साथ हमेशा अच्छे सम्बन्ध रहे हैं । नई जनता सरकार की यह भरसक कोशिश रही है कि इसके सम्बन्ध पड़ोसियों के साथ खासतौर पर अच्छे हों । इस देश में राजनीतिक कई दफा मोड़ तोड़ किये गये, पड़ोसियों के साथ झगड़ा करने के लिये यहां से ही बहुत सी बातें कही गई । रूस के खिलाफ प्रचार हमेशा तेज रहता है, इसी तरह चीन

खिलाफ भी। मैं समझता हूं चीन को हमेशा दुश्मन की कतार में खड़ा रखना यह कोई लियाकत या सूझ की बात नहीं है। चीन भी हमारा दोस्त हो सकता है। हमेशा चीन को दुश्मन कहा जाना और वहां छोटी छोटी बातें होने पर उसको बहुत बड़े विरोध के रूप में इस देश में पेश करना यह कोई ज्यादा फायदेमन्द नहीं रहेगा भविष्य में। यह सरकार क्या चाहती है ? आखिर चीन हमेशा से आक्रमणकारी नहीं रहा है। पाकिस्तान ने हमारे पर आक्रमण किये, मगर अब हम उसके दोस्त बने। आज माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वाजपेयी जी को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध कायम किये और कितने नजदीक लाये। चीन के लोगों ने अपनी गरीबी दूर करने के लिये लड़ाई लड़ी, चीन के लोग बहादुरी से लड़े। वहां के लोगों ने अपने यहां से गरमायेदारी को खत्म किया, और आदमी के हाथ से आदमी की लूट को चीन में खत्म किया गया है। हम चाहते हैं कि उस देश के लोग ईमानदारी से रहें, अच्छाई से रहें, हमारे उनके अच्छे सम्बन्ध रहें। मगर कुछ बातों में बाज दफा जब तीसरी शक्ति अपनी टांग फंसा देती है तो हालात वैसे नहीं रहते हैं जैसे कि हम चाहते हैं। अमरीका एक तरफ हमसे दोस्ती की बात करता है मगर अमरीका का यह प्रयास रहता है कि हर जगह दो आदमियों को लड़ाते रहो ताकि बीच में अमरीका का काम चलता रहे। इसलिये हम चाहते हैं कि हथियारों का विस्तार रुके, यह सरकार भी इस पर जोर देती है हथियारों के विस्तार पर रोक लगे और हथियार संसार में न बनें। यह सरकार यह भी चाहती है कि दुनिया में अमन हो और एक दूसरे के साथ सहयोग से रहें।

मैं मंत्री जी से दो, तीन बातें पूछना चाहता हूं। पहली तो यह कि अमरीका से फ्रांस के जरिये जो न्यूक्लियर शक्ति वहां जा रही है उसके बारे में जो देश में चिन्ता पैदा हो गई है उसके सम्बन्ध में क्या विदेश मंत्री जी जब चीन जायेंगे तो क्या इस विषय को उठायेंगे ?

(2) क्या आपने अमरीका के राजदूत को बुला कर भारत सरकार की ओर से अपना प्रोटेस्ट लाज किया है ?

(3) भविष्य में आप अमरीका के साथ अड़ोस पड़ोस के देशों के बारे में जो उसकी जंगी हथियारों की नीति है उसके बारे में कोई डीटेल्ड वार्तालाप करने के लिये डेलीगेशन का यहां आना या यहां से डेलीगेशन वहां भेजने का आप ख्याल रखते हैं ? यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

13 hrs.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं पीकिंग जाऊंगा, तो सभी प्रश्नों पर चर्चा होगी और उनमें यह प्रश्न भी आ सकता है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इस मसले का सम्बन्ध अमरीका से अधिक है, क्योंकि अमरीका ऐसी टेकनालोजी फ्रांस के जरिये चीन को दे रहा है, जिसको औरों को देते समय वह फुल-स्कोप सेफगार्ड्स की बात करता है। अगर सैनेटर फ्रेंक चर्च का वक्तव्य सही है, तो चीन के मामले में वह उस सेफगार्ड पर बल देने के लिए तैयार नहीं है जैसा कि मैं ने अपने पहले उत्तर में कहा है, इस सम्बन्ध में हम अमरीकी दूतावास से सम्पर्क बनाये हुए हैं, और अगर इस करार को अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो फिर कूटनीतिक दृष्टि से जो भी कदम आवश्यक होगा, वह हम उठायेंगे।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने के प्रयत्नों में कभी कभी बाधा पैदा करने की कोशिश की जाती है। यह तो भारत और पड़ोसी देशों का कर्त्तव्य है कि इस प्रकार की बाधाओं को ताक पर रख कर, और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, अपने सम्बन्धों को सुधारें और उनको मजबूत करें। वर्तमान सरकार सभी पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए उत्सुक है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर हम किसी एक देश के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाना चाहते हैं, तो वह किसी तीसरे देश की कीमत पर बनाना नहीं चाहते हैं, और इस लिए सम्बन्ध सामान्य बनाने की प्रक्रिया और देशों के साथ हमारे सम्बन्धों को कमजोर करने के लिए नहीं होगी। उन सम्बन्धों को मजबूत रखते हुए हम पड़ोसी देशों के साथ अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाना चाहते हैं।

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Committee on Absence of Members from the sittings of the House in their Ninth Report have recommended that leave of absence be granted to eight Members, namely, Thakur Girija Nandan Singh, Sarvashri T. A. Pai, Dharmasinhbhai Patel, Keshavrao Dhondge, K. S. Chavda, Annasaheb Magar, Krishna Chandra Halder and Dr.